'रॉयल्टी वसूली सख्ती से हो, अवैध खनन को रोकें'

मुख्यमंत्री भजन लाल ने रविवार को खनन विभाग की समीक्षा बैठक ली

- उन्होंने कहा कि नवीन सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का समावेश कर विभाग अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम करे। सी सी टी वी कैमरे, ड्रोन सर्वे व मालवाहक वाहनों की सख्त चैकिंग सुनिश्चित करें।
- मुख्यमंत्री ने ओडिशा सहित अन्य राज्यों में खनन क्षेत्र में क्रियान्वित श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों को राजस्थान में लागू करने की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर खनन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने खनन विभाग को नये खनन क्षेत्रों की खोज में तेजी लाने तथा नीलामी प्रक्रिया को और गति देने के निर्देश दिए।

जयपुर, 6 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खनिज सम्पदा का समुचित दोहन करते हुए राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रॉयल्टी वसूली के प्रकरणों में सख्ती से नियमानुसार कार्यवाही की जाए। साथ ही, खनन अधिनियमों और नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम की जाए।

शर्मा रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर खनन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा यहां खनन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने खनन विभाग को नये खनन क्षेत्रों की खोज में तेजी लाने तथा नीलामी प्रक्रिया को और गति देने के निर्देश दिए। शर्मा ने कहा कि नीलाम किए गए ब्लॉक्स में खनन कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए ताकि उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप समय पर पूर्ति सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के राजस्व में खनन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में खनन विभाग समयबद्ध रूप से तय राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करे। इस कार्य में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

शर्मा ने कहा कि नवीन सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों का समावेश करते हुए विभाग अवैध खनन पर प्रभावी रोकथाम करे।

उन्होंने सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन सर्वे और मालवाहक गाड़ी की सख्त चेकिंग सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-सैंड पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ ही गुणवत्तापूर्ण भवन निर्माण सामग्री का एक बेहतरीन विकल्प है। इसे व्यापक रूप से प्रोत्साहित किया जाए ताकि बजरी के दोहन में कमी आए। साथ ही, शर्मा ने क्रशर डस्ट के उपयोग को भी प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने नए ब्लॉक्स की नीलामी की संभावनाएं तलाशने, डीएमएफटी और एनएमईटी से संबंधित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। साथ ही, उन्होंने ओडिशा सहित अन्य राज्यों में खनन क्षेत्र में क्रियान्वित श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों का अवलोकन कर इन्हें राजस्थान में लागू करने की संभावना पर कार्य करने के लिए भी निर्देशित किया।

'हम हिंदी विरोधी नहीं, प्राथमिक शिक्षा में इसे थोपने के खिलाफ हैं'

- उद्धव ठाकरे गुट ने महाराष्ट्र में हिन्दी भाषा पर उठे विवाद पर अपना रुख स्पष्ट किया।

मुंबई, 6 जुलाई। महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया था कि कक्षा 1 से 5 तक हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, लेकिन विरोध के बाद सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए शनिवार को उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे सालों बाद एक मंच पर आए। हालांकि, अगले ही दिन रविवार को उद्धव की शिवसेना ने साफ किया कि उनकी पार्टी हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है। पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा तमिलनाडु में जो हिंदी विरोध है, उसमें वे न हिंदी बोलते हैं और न दूसरों को बोलने देते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हमारा ऐसा कोई रुख नहीं है। हम हिंदी बोलते हैं, यहां हिंदी फिल्में, थिएटर और संगीत भी है। हमारी लड़ाई सिर्फ प्राथमिक शिक्षा में हिंदी थोपने के खिलाफ है।

राउत ने कहा कि डीएमके नेता एम.के. स्टालिन को उनके संघर्ष के लिए शुभकामनाएं, लेकिन हमारी सीमाएं स्पष्ट हैं। स्टालिन ने जवाब में कहा, हमारी हिंदी विरोधी लड़ाई महाराष्ट्र पहुंची

उद्धव और राज ठाकरे को एक साथ मंच पर देखकर स्टालिन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक्स पर लिखा कि तमिलनाडु और डीएमके द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ी गई हिंदी विरोधी लड़ाई अब बाहर निकलकर महाराष्ट्र तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में हुई विजय रैली का उत्साह और जोश हमें गर्व और उम्मीद से भर देता है। हालांकि उद्धव गुट ने स्टालिन के समर्थन को सराहा, लेकिन स्पष्ट किया कि वे हिंदी भाषा के विरोध में नहीं हैं, केवल शिक्षा में जबरन थोपने के खिलाफ हैं।

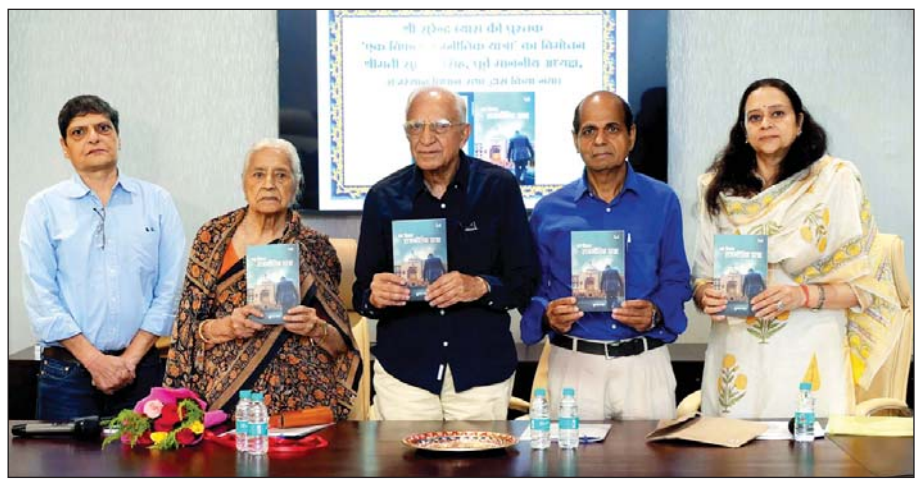

राजस्थान की पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने रविवार को पूर्व मंत्री सुरेन्द्र व्यास की पुस्तक "एक विफल राजनीतिक यात्रा" का विमोचन किया।

राजस्थान में मुख्यमंत्री व विपक्ष में सहयोग की परम्परा रही है - सुरेन्द्र व्यास

पूर्व स्पीकर सुमित्रा सिंह ने पूर्व मंत्री सुरेन्द्र व्यास की पुस्तक "एक विफल राजनीतिक यात्रा" का विमोचन किया

- सुमित्रा सिंह ने कहा कि व्यास ने विधानसभा में खूब मेहनत से ज्वलंत मुद्दे उठाये पर, विडम्बना यह रही है कि सुर्खियां तो खूब बटोरीं पर वांछित परिणाम तक नहीं पहुंच पाये।
- सुरेन्द्र व्यास ने भैरोंसिंह शेखावत के दामाद के मामले में उनके लिए संकट की स्थिति पैदा कर दी। जब व्यास विशेषाधिकार द्वारा महाभारत के अभिमन्यु की तरह पिट गये, तब भी उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया।

जयपुर 6 जुलाई। राजस्थान के पूर्व मंत्री सुरेन्द्र व्यास की पुस्तक "एक विफल राजनीतिक यात्रा" का विमोचन रविवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह ने किया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के चिन्तन कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्य अतिथि सुमित्रा सिंह ने पुस्तक का विमोचन करते हुए कहा कि 4 बार मेरे साथ विधायक रहे व्यास ने विधानसभा में ज्वलंत मुद्दों को बड़ी शिद्दत के साथ उठाया और उन्हें परिणाम तक पहुँचाने के लिए खूब मेहनत की। कुछ मामलों को तो वे सुप्रीम कोर्ट तक ले गये लेकिन विडम्बना यह रही कि उन मामलों ने सुर्खियाँ तो खूब बटोरी लेकिन वांछित परिणाम तक नहीं पहुंच पाए। पुस्तक का शीर्षक "एक विफल राजनीतिक यात्रा" व्यास की इसी निराशा का परिणाम है जिसे इन्होंने भी स्वीकार किया है।

राजस्थान की महिलाओं में सर्वाधिक 9 बार विधायक रहीं 95 वर्षीय सुमित्रा सिंह ने कहा कि सुरेन्द्र व्यास सदन में बड़ी बेबाकी और तर्कों के साथ अपनी बात कहते थे जिसे बड़ी गम्भीरता से सुना जाता था। उन्होंने व्यास को पुस्तक के लिए बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि ये ऐसी पुस्तकें और लिखें जिनसे नये राजनीतिज्ञों को सीखने का मौका मिले।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान विधानसभा में सदन के बाहर राजनेताओं के आपसी सम्बन्ध आज के समान कटु नहीं बल्कि मधुर होते थे। व्यास ने नौवीं विधानसभा के कार्यकाल में भैरोंसिंह शेखावत के दामाद के मामले में उनके लिए संकट की स्थिति पैदा कर दी लेकिन जब व्यास विशेषाधिकार हनन के एक मामले में सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा महाभारत के अभिमन्यु की तरह चारों ओर से घिर गये तो भी अपने सिद्धान्तों से समझौता नहीं किया और माफी नहीं मांगी। ऐसी स्थिति में भी शेखावत ने व्यास की सदस्यता रद्द नहीं होने दी।

इस अवसर पर व्यास ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के बीच आपसी सहयोग के अनकहे समझौते की परम्परा रही है। पुस्तक में ज्वलंत उदाहरण देकर ऐसे समझौतों को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है।

विधानसभा के पूर्व शोध एवं संदर्भ अधिकारी डॉ. कैलाश चन्द सैनी ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए पुस्तक, लेखक और मुख्य अतिथि के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला तथा अंत में लेखक की भावनाओं के अनुकूल सभी का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर लेखक व्यास की पुत्री डॉ. शिप्रा कुमार और दामाद संजय कुमार भी मौजूद थे।

पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के भतीजे के पुत्र की सड़क हादसे में मौत

मृतक रुद्रवीर अपने रिसॉर्ट से 30 किलोमीटर दूर जैसलमेर केक लाने जा रहे थे

- अशोक गहलोत के भतीजे अजय लम्बे समय से जैसलमेर में रहते हैं और दामोदरा गांव में बी एड कॉलेज का संचालन करते हैं। दामोदरा में ही उन्होंने एक रिसॉर्ट बना रखा है जहां शनिवार को जन्मदिन की पार्टी का आयोजन था।

जोधपुर, 6 जुलाई (का.सं.)। जैसलमेर में शनिवार रात हुए एक सड़क हादसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक रिश्ते के पोते की मौत हो गई। मृतक पूर्व सीएम अशोक गहलोत के भतीजे का पुत्र था।

जानकारी के अनुसार इंदिरा इंडोर स्टेडियम के पास कार पलटने से रुद्रवीर (21) पुत्र अजय गहलोत की मौत हो गई, तथा हादसे में उसके चार दोस्त घायल हो गए। सभी को निजी वाहन की मदद से जवाहर हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने रुद्रवीर को मृत घोषित कर दिया। चारों घायलों का इलाज शुरू हो गया है। गंभीर रूप से घायल कुणाल पुत्र श्याम सिंह को जोधपुर रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार रुद्रवीर के एक दोस्त का शनिवार को जन्मदिन था। रुद्रवीर का जैसलमेर से तीस किमी दूर दामोदरा गांव के पास एक रिसॉर्ट है, जहां जन्मदिन मनाया जाना था। कुल दस दोस्त अलग-अलग गाड़ियों से जैसलमेर से वहां पहुंचे। रात करीब ग्यारह बजे सभी को याद आया कि वे केक लाना भूल गए हैं। तब रुद्रवीर अपनी कार में चार दोस्तों के साथ दामोदरा से केक लेने जैसलमेर रवाना हुआ। जैसलमेर आते समय रात करीब 11.30 बजे इंदिरा इंडोर स्टेडियम के पास तेज गति से दौड़ रही कार निर्माणाधीन सड़क पर अचानक पलट गई। दो बार पलटने के बाद कार सड़क के पास उलट गई।

गाड़ी रुद्रवीर चला रहा था और गाड़ी के पलटने पर वो गाड़ी से बाहर आकर गिरा और किसी पत्थर से टकराने से गंभीर रूप घायल हो गया।

हादसे के बाद राह से गुजर रही एक बोलेरो गाड़ी में सवार लोगों ने हादसाग्रस्त गाड़ी के शीशे तोड़कर सभी को बाहर निकाला और रुद्रवीर सहित सभी को जवाहर अस्पताल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार मृतक रुद्रवीर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भतीजे अजय गहलोत का बेटा था। अजय गहलोत लम्बे समय से जैसलमेर में रहते हैं और दामोदरा गांव में बीएड कॉलेज का संचालन कर रहे हैं। दामोदरा में ही उन्होंने एक रिसॉर्ट भी बना रखा है, जहां शनिवार को जन्मदिन की पार्टी का आयोजन हुआ था। परिजन रुद्रवीर का शव लेकर जोधपुर आए और आज दोपहर उसका अंतिम संस्कार किया गया।

अमित शाह ने भारत के पहले सहकारी वि.वि. का भूमि पूजन किया

नई दिल्ली, 06 जुलाई। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के आणंद में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय "त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी" का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने त्रिभुवन दास पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस यूनिवर्सिटी से सहकारिता में भाई-भतीजावाद खत्म होगा, पारदर्शिता आएगी और सहकारी यूनिवर्सिटी से प्रशिक्षण लेने वालों को रोजगार मिलेगा।

शाह ने कहा, इस यूनिवर्सिटी में युवाओं को तकनीकी विशेषज्ञता, अकाउंटेंसी, वैज्ञानिक अप्रोच और मार्केटिंग के साथ-साथ सहकारिता के संस्कार भी सीखने को मिलेंगे। एक सहकारी नेता हर सदस्य की भलाई के लिए जब काम करता है, तो राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में कितना बड़ा योगदान देता है, इसके आदर्श उदाहरण त्रिभुवन दास जी थे। इस लिए इस यूनिवर्सिटी के लिए सबसे उचित नाम 'त्रिभुवनदास है।

उन्होंने कहा, त्रिभुवन दास के ही विजन के कारण दुनियाभर की निजी डेयरियों के सामने आज हमारे देश की कोऑपरेटिव डेयरी सीना तानकर खड़ी हैं।

हरियाणा असिसटैंट प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाये- सुरजेवाला

उन्होंने आरोप लगाया कि कई विषयों में प्रश्न पत्रों की सील टूटी मिली व गंभीर अनियमितताएं सामने आईं

- सुरजेवाला ने कहा कि 2024 में 26 विषयों में 2,424 पदों के लिये डेढ़ लाख अभ्यार्थियों ने आवेदन किया था।

हिसार, 6 जुलाई। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने असिस्टैंट भर्ती प्रक्रिया को लेकर हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) पर बड़ा हमला बोला है। आज हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी और एचपीएससी चेयरमैन आलोक वर्मा पर सीधा आरोप लगाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा कराने की मांग की। सुरजेवाला ने आयोग को हेराफेरी सर्विस कमीशन करार दिया और न्यायिक जांच की मांग करते हुए आरोप लगाया कि एचपीएससी में लगातार पेपर लीक, सवालों की कॉपी और आंसर की में गड़बड़ियों जैसी गंभीर अनियमितताएं सामने आ रही हैं।

सुरजेवाला ने बताया कि 29 मई 2025 को पोलिटिकल साइंस का पेपर लिया गया, जिसकी सील टूटी हुई पाई गई। 1 जून को आयोजित हिंदी के पेपर में भी यही स्थिति रही। 3 जून को भारी विरोध के बाद पेपर रद्द किया गया।

उन्होंने आरोप लगाया कि हिंदी के प्रश्न पत्र में 27 सवाल पूरी तरह गलत थे। बाद में रिवाइज़ आंसर की में भी सही उत्तरों को गलत बताया गया, जिससे अभ्यर्थियों को भारी नुकसान हुआ।

सुरजेवाला ने ज्यॉग्राफी के पेपर में बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से सीधे 32 सवाल कॉपी किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि आयोग के चेयरमैन आलोक वर्मा खुद बिहार से हैं, जिससे इस नकल की संभावना और भी मजबूत होती है।

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि 2019 के बाद से हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भर्ती नहीं हुई। अगस्त 2024 में 26 विषयों में 2,424 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें लगभग डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। लेकिन भर्ती शुरू होते ही पेपर लीक, सवालों की नकल और आंसर की की गलतियों के चलते पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में आ गया।

सुरजेवाला ने पूरे मामले की जिम्मेदारी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी पर डालते हुए हाईकोर्ट की सिटिंग जज से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है।

अवैध ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

रही है। इसीलिए मैं देश के लोगों को अवैध प्रवासियों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश देने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। मुरासिंह ने दावा किया कि अनियंत्रित घुसपैठ के कारण त्रिपुरा के अपने लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहे हैं।

मोदी ने दलाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तिब्बत के अमदो के तकत्सेर में एक छोटे से गांव में किसान परिवार में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम तेनज़िन ग्यात्सो था और दो वर्ष की आयु में उन्हें 13वें दलाई लामा, थुबतेन ग्यात्सो के पुनर्जन्म के रूप में पहचाना गया।

चीनी सेना द्वारा 1959 में, ल्हासा में तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह के क्रूर दमन के बाद, दलाई लामा भारत आ गए थे और तभी से यहीं रह रहे हैं।

नकाबपोश युवकों ने मुस्लिम परिवार के दो मकानों में आग लगाई

टेंडर के बाद स्वीकृति के लिए वित्त विभाग फाइल भेजने की व्यवस्था समाप्त

मुख्यमंत्री द्वारा लागू की गयी नई व्यवस्था से विकास कार्यों में तेजी आयेगी

- भिवानी जिले के एक गांव की घटना में पुलिस व फायर ब्रिगेड ने तुरंत कार्यवाही की
- अभी आग लगाने वालों का पता नहीं चल पाया है।
- पिछली सरकार में यह व्यवस्था शुरू की गयी थी कि वित्त विभाग केवल सैद्धांतिक स्वीकृति देता था, विभागों को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए फाइल वित्त विभाग को भेजनी पड़ती थी। इससे 15 से 30 दिन का अतिरिक्त समय लगता था।

भिवानी, 6 जुलाई। हरियाणा के भिवानी जिले के ढ णी मांहू गांव की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने मुस्लिम परिवार के दो मकानों का सामान पहले बाहर फेंक कर मकान और सामान को आग के हवाले कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी बुलाई गईं और आग पर काबू पाया गया।

भिवानी के ढ णी मांहू गांव में हुसैन नामक शख्स के दो मकानों के सामान को कुछ नकाबपोश युवकों ने पहले बाहर फेंका और फिर आग के हवाले कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो बड़ी संख्या में पुलिस बलों ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। वहीं जिस घर में आग लगाई गई, उस घर के परिवार का कोई सदस्य मौके पर नहीं मिला है। पुलिस ने भी आसपास के लोगों से पूछताछ की है। ख़बर लिखे जाने तक आग लगाने वालों और परिवार के लोगों का पता नहीं चल सका है। अक्षय नाम के ग्रामीण के अनुसार, दर्जनों की तादाद में नकाबपोश युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने अपने मुंह ढंक रखे थे। कुछ लोगों ने हथौड़ा ले रखा था जिससे उन्होंने तोड़फोड़ की। इसके बाद नकाबपोश मौके से फरार हो गए।

जयपुर, 6 जुलाई। आमजन को भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सुशासन देने के लिए संकल्पित राज्य सरकार, विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक त्वरित रूप से पहुँचाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी नीति के तहत मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास कार्यों में तेजी लाने तथा प्रक्रिया में लगने वाले समय को न्यूनतम करने के लिए राज्य में अब नई व्यवस्था लागू की गई है।

टेंडर के बाद प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए कार्यकारी विभाग द्वारा वित्त विभाग को फाईल भेजने की व्यवस्था अब समाप्त कर दी गई है। गत सरकार के समय शुरू हुई इस प्रक्रिया के कारण विकास कार्य शुरू होने में अनावश्यक विलंब हो रहा था। जिसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में यह नई व्यवस्था लागू की गई है।

विकास कार्यों की घोषणा कर धरातल पर निर्माण कार्य शुरू करने में जानबूझ कर देरी करने की नीयत से गत सरकार के समय व्यवस्था की गई कि कार्यकारी विभाग जब कार्य की स्वीकृति के प्रस्ताव के साथ वित्त विभाग को भिजवाता था, तब वित्त विभाग इस स्वीकृति के बजाय कार्य की केवल सैद्धांतिक स्वीकृति देता था। इसके बाद प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति के लिए संबंधित कार्यकारी विभाग को प्रस्ताव पुन: वित्त विभाग को भेजना पड़ता था।

इस दोहरी प्रक्रिया में 15 से 30 दिन का अतिरिक्त समय लग रहा था। इससे एक ओर विकास कार्य की लागत बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर आमजन को इनका समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार प्रक्रिया में संशोधन कर इसे प्रभावी बना दिया गया है। अब कार्यकारी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत होते ही निविदा उपरान्त कार्यादेश जारी करने के लिए कार्यकारी विभाग को ही सक्षम बना दिया गया है।

कार्यकारी विभाग निविदा के उपरांत कार्यादेश राशि के आधार पर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृत राशि को स्वयं ही पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे।

अत: प्रक्रिया के दूसरे चरण में पत्रावली वित्त विभाग को प्रेषित करने की आवश्यकता नही रहेगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से विकास कार्यों में तेजी आएगी और निर्धारित समय सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ विकास कार्य करवाने का राज्य सरकार का संकल्प धरातल पर साकार हो सकेगा।

कांग्रेस- समाजवादी पार्टी गठबंधन अभी टूटा नहीं है- सलमान खुर्शीद

मुजफ्फरनगर, 06 जुलाई। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन अभी नहीं टूटा है। जब हमने साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो हमें जो सफलता मिली। उस परिणाम को सबने देखा है। इस सफलता में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की भूमिका सभी समझते हैं। कांग्रेस हाईकमान इसे ध्यान में रखते हुए ही आगे कोई फैसला लेगा। मुज्फ्फरनगर में मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए सलमान खुर्शीद ने ये बात कही। सलमान खुर्शीद ने कहा कि इस गठबंधन का रिजल्ट सबके सामने है। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। ज्ञातव्य है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में इस गठबंधन ने भाजपा को कड़ी टक्कर देते हुए शानदार प्रदर्शन किया था। 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। सपा को 37 सीटों पर सफलता मिली जबकि कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की।

युद्ध बंधकों पर हमास से बात करने इज़रायली दल कतर जायेगा

इज़रायली प्रधानमंत्री ने कतर के प्रस्ताव के आधार पर वार्ता करने के लिये सहमति जताई

यरूशलम, 06 जुलाई। इज़रायली प्रधानमंत्री बैन्जामिन नेतन्याहू ने हमास के साथ युद्ध बंधकों पर बातचीत करने के लिए रविवार को एक वार्ता दल को कतर जाने का निर्देश दिया है। इज़रायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।

बयान के अनुसार, स्थिति का आकलन करने के बाद इज़रायल ने इस वार्ता के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है । वह गाज़ा में बंधक बनाए गए इज़रायलियों की रिहाई के लिए कतर के प्रस्ताव के आधार पर बातचीत जारी रखने पर सहमत हो गया है। प्रस्ताव में 60 दिन का युद्ध विराम, पांच चरणों में 10 इज़रायली बंधकों की रिहाई, 18 बंधकों के शवों को सौंपना तथा इज़रायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल है।

बयान में कहा गया कि इज़रायल को कल शाम जानकारी दी गई कि हमास ने प्रस्ताव में बदलाव की मांग की है जो इज़रायल को अस्वीकार्य है। इज़रायली सरकार के स्वामित्व वाले कान टीवी न्यूज़ ने कहा कि हमास ने जो बदलाव किए हैं उनमें युद्ध समाप्त करने के लिए वार्ता में शीघ्र बदलाव की गारंटी, समझौते की गारंटी देने वाले देशों में तुर्की को शामिल करना, मानवीय सहायता संबंधित विवरण और गाज़ा पट्टी से इज़रायली सैन्य बलों की वापसी शामिल है।उल्लेखनीय है कि चार जुलाई को हमास ने एक बयान में कहा था कि उसने गाज़ा युद्ध विराम प्रस्ताव पर मध्यस्थों को सकारात्मक जवाब दिया है और वह इस रूपरेखा को लागू करने की प्रकिया संबंधी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908